

महानता कभी
ना गिरने में
नहीं बल्कि हर बार
गिरकर उठने में है।
- अज्ञात

अर्थव्यवस्था में गति लाने की कोशिशें

इसके अलावा उन्होंने नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों के पुनः वित्तपोषण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की। इस समय सबसे बड़ी चुनौती बदहाल औद्योगिक इकाइयों को वापस ठिकाने पर लाने की है।

ललित काण्डपाल।

कोरोना वायरस के संकट के कारण सुस्त पड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था में गति लाने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को इसके लिए कई घोषणाएं की हैं। उसने रिजर्व रेपो रेट 0.25 फीसदी से घटाकर 3.75 फीसदी कर दिया है। रिजर्व रेपो रेट उस ब्याज दर का नाम है, जो बैंकों द्वारा अपना पैसा रिजर्व बैंक में रखने पर उन्हें हासिल होती है। खुद रिजर्व बैंक की उधारी दर रेपो रेट में कई कटौतियां पिछले कुछ महीनों में की जा चुकी हैं और इस बार इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रिजर्व रेपो दर घटने से बैंक अपनी नकदी को कारोबार में ही लगाने को बाध्य होंगे और फौरी तौर पर इसे रिजर्व बैंक में रखना उनके लिए ज्यादा घाटे का

सौदा हो जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) के जरिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराएगा। यह काम किस्तों में किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थानों के पुनः वित्तपोषण के लिए 50,000 करोड़ रुपये की सहायता देने की भी घोषणा की। इस समय सबसे बड़ी चुनौती बदहाल औद्योगिक इकाइयों को वापस ठिकाने पर लाने की है।

कोरोना से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन ने उनकी कमाव तोड़ दी है। फंडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) का अनुमान है कि

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से उद्योग जगत को हर रोज 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है और औद्योगिक इकाइयों के बंद होने से 4 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। इसलिए एसोचोम ने पिछले दिनों कहा कि अर्थव्यवस्था को कम से कम 14 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की जरूरत है, जिसमें सरकारी कंपनियों का 2.02 लाख करोड़ रुपये का उर्वरक बकाया और अन्य भुगतान शामिल हैं।

कई छोटी-छोटी इकाइयों को तत्काल सहायता की जरूरत है। अगर बैंकों से उन्हें ऋण मिल सके तो उनका कामकाज पटरी पर लौट सकता है। रिजर्व बैंक का मकसद यही है। हालांकि यह भी कहा

जा रहा है कि उद्योगों में उत्पादन शुरू करने से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या उनकी सेवाओं और सामानों के लिए मांग पैदा करने की है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इसके लिए किसानों, दुकानदारों और बहुत छोटे कारोबारियों को पैकेज देने होंगे।

सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई सुविधाओं की घोषणा की है लेकिन बाजार में हलचल बढ़ाने के लिए मिडल क्लास का कर्ज लेना जरूरी है। निर्माण उद्योग में तेजी और होम लोन में बढ़ोतरी परस्पर जुड़ी हुई चीजें हैं। हालांकि यह तभी होगा जब मध्यवर्ग की नौकरियां सुरक्षित रहें। उसकी बेरोजगारी या सैलरी कट अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। सरकार और उद्योग जगत को आपसी समझ से इसका निदान खोजना होगा।

समझ

अशोक वोहरा।

वैज्ञानिक यह काम 1992 से कर रहे हैं और इसके जरिये उन्होंने न सिर्फ आकाशगंगा के केंद्र की, बल्कि खुद तारा भौतिकी की भी समझ बढ़ाई है। हमारे सूरज का 15 गुना वजन

धर्म-दर्शन



एस-2 तारा कुछ मामलों में विचित्र है। तारों का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा होता है, लेकिन एस-2 की कक्षा ग्रहों जैसी सरल है। सैजिटेरियस ए स्टार का चक्कर यह उससे अधिकतम 970 एयू और न्यूनतम 120 एयू दूर रहकर लगाता है। धरती से सूरज की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट (एयू) कहते हैं। इस रास्ते पर एस-2 की गति बदलती रहती है और जब-तब इसे एक करोड़ किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से चलते देखा गया है। हाल में इस तारे के दो चक्करों के बीच ही इसके कक्षीय अक्ष (ऑर्बिटल एक्सिस) में स्पष्ट खिसकाव दर्ज किया गया, जिसका सौरमंडल में कोई हिसाब सदियों में ही मिल पाता है।

संपादकीय

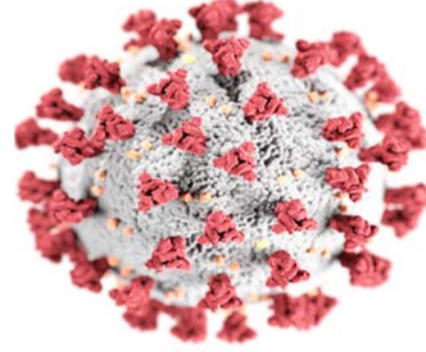
यूरोपीय एकता तार-तार

कोरोना के चलते यूरोपीय एकता तार-तार होती दिख रही है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में उभरे जिस संघवाद के चलते यूरोपीय संघ सामने आया, वह खतरे में है। ब्रिटेन के अलग होने को अपवाद मान लें तो यूरोप की मुद्रा और संसद तक एक है। लेकिन कोरोना ने उन्हें बांट दिया है। इटली और स्पेन इस महामारी से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं। फ्रांस और ब्रिटेन में भी विभीषिका कम नहीं है। लेकिन इससे जूझने में यूरोपीय संघ के बीच सहयोग नहीं दिख रहा है। उसमें प्रस्ताव आया कि चंदे की रकम से कोरोना की विभीषिका से जूझ रहे देशों के लिए फंड बनाया जाए, लेकिन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की अगुआई में नीदरलैंड, फिनलैंड और ऑस्ट्रिया ने इसका विरोध कर दिया। जाहिर है कि इसका गहरा असर यूरोप के सियासी संतुलन पर भी पड़ेगा। कोरोना से लड़ाई में कम्युनिस्ट शासन वाले उस क्यूबा का इटली सहयोग ले रहा है, जिसका अमेरिकी अगुआई में वह हाल के दिनों तक विरोध करता रहा है। यानी कुछ यूरोपीय देश चीन और क्यूबा के करीब जा रहे हैं। चीन ऐसी ही मदद रूस को भी दे रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रहे ईरान को मदद देने में भी चीन आगे है, हालांकि भारतीय फार्मा कंपनियों की दवाएं भी वहां पहुंची हैं।

वैश्विक आर्थिक ताकतों के बरक्स ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने समानांतर आर्थिक समूह ब्रिक्स बना रखा है। कोरोना बाद की राजनीति में इसमें चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। जिस तरह इस समूह के मजबूत स्तंभ ब्राजील ने चीन पर हमला बोला है, उससे यही संकेत मिलता है। देर-सबेर भारत को अपने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए ब्राजील के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा।

एक बात तय लग रही है कि कोरोना वायरस सिर्फ मानवता पर गहरी चोट देकर ही नहीं जाने वाला है, बल्कि यह दुनिया के शक्ति संतुलन और विश्व-व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाने जा रहा है।

बढ़ रही तनातनी



उमेश चतुर्वेदी।

मानवता का इतिहास अदम्य जीवत की कहानी है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इतना तो कहा ही जा सकता है कि अतीत की दूसरी महामारियों की तरह कोरोना पर भी काबू पा लिया जाएगा। महामारियों की कहानी में नई वैश्विक व्यवस्थाओं की महागाथा भी सुनाई देती रही है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि कोरोना संकट के बाद क्या दुनिया वैसी ही रहेगी, जैसी पहले थी? पूरी दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी के महाबंदी या लॉकडाउन में बंध जाने के बाद धरती, उसके वायुमंडल और मानवीय सोच में दिख रहे बदलाव भावी परिदृश्य के संकेत देने लगे हैं। एक बात तय लग रही है कि कोरोना वायरस सिर्फ मानवता पर गहरी चोट देकर ही नहीं जाने वाला है, बल्कि यह दुनिया के शक्ति संतुलन और विश्व-व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाने जा रहा है।

प्लेग की महामारी ने जहां यूरोप को अंधकार युग से बाहर किया, वहीं दुनिया को सीवर सिस्टम की अवधारणा दी। विश्व युद्ध की विभीषिका और उससे उपजी महामारियों ने दुनिया को दो ध्रुवों में बांटने, राष्ट्रों की सीमाओं को बंद करने और मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था की वैश्विक स्वीकार्यता की पूर्व पीठिका रची। कुछ

उसी अंदाज में कोरोना की भयावहता भी दुनिया को बदलने जा रही है।

शीत युद्ध के बाद से ही अमेरिका दुनिया का दादा बना हुआ है। रूस के एक हद तक अपने खोल में सिमट जाने के बाद उसको चुनौती देने की कोशिश में चीन लगातार जुटा रहा है। लेकिन अभी चीन बचाव की मुद्रा में है क्योंकि उसके वूहान शहर से निकले कोविड-19 से ही पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लापरवाही बरतने और सूचनाएं छुपाने के लिए दुनिया चीन को दोषी मान रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप तो इसे चीनी वायरस ही कहते रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का रुख भी ऐसा ही रहा है। लेकिन इस पर चीन कभी गुस्से में तो कभी कूटनीतिक तौर पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है। साफ

है कि वह कोरोना को एक अवसर के रूप में देख रहा है और नहीं चाहता कि उसकी तीखी प्रतिक्रिया से दुनिया उसके खिलाफ गोलबंद हो जाए।

अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश अभी इस महामारी से जूझ रहे हैं, लिहाजा उनकी पहली कोशिश इससे अपनी ज्यादा से ज्यादा जनता को बचाना है। इसीलिए वे अपना सारा ध्यान और ताकत इस महामारी से निपटने पर लगाए हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि इसपर काबू पाने के तुरंत बाद वे चीन को घेरने की कोशिश करेंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उसके खिलाफ मामला चलाने की तैयारियों की भी सुगबुगाहटें हैं। इन देशों के नागरिक समूहों की ओर से ऐसी मांगें उठने लगी हैं। इसी साल के आखिर में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अगर ट्रंप को दोबारा मौका मिलता है, तो वे चीन से हिसाब चुकता करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी गोलबंदी में दुनिया के ज्यादातर देशों की जुटने की संभावना होगी। लेकिन चीन की आर्थिक ताकत के चलते अमेरिका विरोधी देशों का खेमा चीन के साथ खड़ा हो सकता है। इसका संकेत तुर्की के कदम से मिलता है, जिसने कोरोना की महामारी से जूझ रहे स्पेन के लिए जा रहे मेडिकल सामान से लदे तीन जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया।

अष्टयोग-5029

	7	4	6	
6	37	29	2	29
2		5	1	3
4	32	29		35
	6		7	2
	33	2	32	6
5		7	4	
				3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है, खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं, गहरे काले वर्ण में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्णों की संख्या का कुल योग होगा, सीधो अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है।

अपना ब्लॉग

भारत के लिए
अवसर

मोहन। इन हालात में चीन में होने वाले वैश्विक निवेश पर असर पड़ना स्वाभाविक है। चीन का निर्यात घट सकता है और इसका फायदा भारत उठा सकता है। कोरोना बाद की वैश्विक व्यवस्था में चीन की बजाय भारत अंतरराष्ट्रीय कंपनियों की पसंदीदा जगह बन सकता है। इसके लिए भारत को तैयार रहना होगा। देश के करीब पचास करोड़ योग्य हाथों को काम देने के लिए उसके पास बड़ा मौका होगा। लेकिन यह सब उसकी तैयारी और चीन की वैश्विक घेरेबंदी पर निर्भर करेगा। चीन को इस भावी गोलबंदी की पूरी आशंका है। वह जानता है कि बदली राजनीति में वह धिर सकता है। इसलिए उसने कोरोना की महामारी से ग्रस्त इटली को सहायता पहुंचाई है और यूरोप के दूसरे देशों में मास्क पहुंचाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने उसके मास्क को बेकार बताते हुए वापस कर दिया है, यह और बात है।

